समांवेशी विकास

[INCLUSIVE GROWTH]

आम आदमी के संदर्भ में, समावेशी विकास का अर्थ आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या देश की कुल आय में समग्र वृद्धि को दर्शाता है। अब, जब तक कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ नहीं पहुंच जाता, तब तक आय में एक मात्र वृद्धि को बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं कहा जा सकता है।

यह वह जगह है जहां समावेशी विकास की अवधारणा तर्क पर आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि बढ़े हुए आय स्तर का लाभ हर सामाजिक तबके, विशेष रूप से गरीब से गरीब लोगों को मिलना चाहिए।

समावेशी विकास का अर्थ है आर्थिक विकास जो रोजगार के अवसर पैदा करता है और गरीबी को कम करने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि गरीबों द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा में आवश्यक सेवाओं तक पहुँच। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना शामिल है। यह एक विकास प्रक्रिया को भी शामिल करता है जो पर्यावरण के अनुकूल विकास है, इसका उद्देश्य सुशासन है और एक लिंग संवेदनशील समाज के निर्माण में मदद करता है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं क्योंकि यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। भारत में सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में से एक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है और प्रवासन को काफी हद तक जांचने में सक्षम हुआ है। इसके अलावा, सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), भारत निर्माण आदि जैसे कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे विकास और अधिक समावेशी हो गया है।

समावेशी विकास की आवश्यकता

पिछले तीन दशकों के दौरान दुनिया के अधिकांश हिस्सों में असमानताएं बढ़ी हैं। जीडीपी, उदार और विस्तारवादी राजकोषीय नीति, बड़े सार्वजनिक ऋण, प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार और अधिक पूंजी का उपयोग करके उत्पादन की प्रकृति में बदलाव, जीडीपी में सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी, प्रतिकूल नीतियों और संस्थानों आदि में कुछ प्रशंसनीय कारण हैं। असमानता के बढ़ने के अलावा, हाल के दशकों में श्रम बाजारों में अन्य गंभीर बदलाव हुए हैं। ये तकनीकी परिवर्तन, बढ़ते प्रवासन, कुछ देशों में उम्र बढ़ने वाले

समाजों और दूसरों में युवा उभार, और रोजगार के पैटर्न को बदलने से उत्पन्न होते हैं। इन परिवर्तनों की दिशा ने अक्सर अर्थव्यवस्थाओं को समावेशिता और सामाजिक न्याय से दूर कर दिया है और ये ताकतें भी विकसित होती रहेंगी। नई 'विघटनकारी' तकनीक और नए वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढाँचे ने 'काम' का चेहरा बदल दिया है। कई मौजूदा नौकरियां लुप्त हो रही हैं और नई उभर रही हैं। राजन ने नौकरियों पर बदलती प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को साझा किया और उल्लेख किया कि रोबोटिक्स और स्वचालन कई नियमित और कुशल नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के लिए, राजन ने आगाह किया कि कृषि और कम उत्पादक उद्योग और सेवाओं की तरह नियमित और कम उत्पादक कार्यों से आगे बढ़ने की जरूरत है और निर्यात, तकनीकी स्टार्टअप, आदि कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में असमानता के अन्य स्थानों में अवसर को जब्त करना है। एक और महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक मुद्दा है। कुल मिलाकर, महिला श्रम शक्ति भागीदारी किसी भी देश में विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है और यहां तक कि एसडीजी ने भी इस लैंगिक अंतर को कम करने का लक्ष्य रखा है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट (एमजीआई) में कहा गया है कि "पूर्ण संभावित" परिदृश्य में महिलाएं पुरुषों की तुलना में श्रम बाजारों में एक समान भूमिका निभाती हैं, जितना कि $ 28 ट्रिलियन, या 26 प्रतिशत, को जोड़ा जा सकता है। 2025 तक वैश्विक वार्षिक जीडीपी। भारत को श्रम शक्ति भागीदारी में समानता से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की उम्मीद है - 2025 तक पूर्ण समानता जीडीपी में 60 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

समावेशी विकास की चुनौतियां

विकास कुछ चुनौतियों में धीमी आर्थिक वृद्धि, तकनीकी विकास और नौकरी विस्थापन आदि शामिल हैं, क्योंकि 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मंदी से बच नहीं पाई है। कुल मिलाकर, वसूली नाजुक और अनिश्चित रही है, और यह कई देशों में बढ़ती नौकरियों घाटे (नई नौकरियों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में घाटे) में परिलक्षित होता है। रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति के साथ, श्रम बाजारों में व्यवधान बहुत बड़ा होने की संभावना है। श्रमिकों के कौशल को बहुत तेज गति से अप्रचलित होने की संभावना है। यह अनुमान है कि 400 मिलियन से 800 मिलियन के बीच व्यक्तियों को स्वचालन से विस्थापित किया जा सकता है और दुनिया भर में 2030 तक नई नौकरियों की तलाश करने की आवश्यकता है। एक ओर, श्रम बाजार में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है; दूसरी ओर धन की एकाग्रता में वृद्धि होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 7 और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि कुल जीडीपी में गिरावट के साथ व्यापक असमानता भी जुड़ी हुई है जो काम करने वाले लोगों को उनके वेतन चेक के माध्यम से जाती है। बेरोजगारी और बेरोजगारी के अलावा, सबसे उन्नत और कुछ उभरते देशों में मजदूरी वृद्धि में महत्वपूर्ण मंदी राष्ट्रीय आय के श्रम हिस्सेदारी में गिरावट के लिए जिम्मेदार है, और यह समग्र घरेलू असमानता और व्यक्तिगत आय असमानता को खिलाती है। कमजोर वृद्धि और निराशाजनक रोजगार सृजन की

स्थिति में, मौद्रिक नीति के हस्तक्षेप कुछ मामलों में व्यापक और अभूतपूर्व भी रहे हैं। बेशक, इसने अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव डाला है, भारत सहित उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी प्रवाह से लाभ मिल रहा है, लेकिन अब दुर्भाग्य से पूंजी के बहिर्वाह से पीड़ित हैं क्योंकि मौद्रिक उत्तेजना का अंत क्षितिज पर दिखाई देने लगता है। इसलिए, इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न नीतिगत साधनों पर विचार करने की आवश्यकता है।

भारत में समावेशी विकास रणनीतियों से पहले की समस्याएँ

भारत जैसे विकासशील देश के लिए, समावेशी विकास की आवश्यकता देश की समग्र प्रगति को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता के लिए सकारात्मक है, 2008- 2009 के परिणामस्वरूप वैश्विक आर्थिक गति और अस्थिर वित्तीय बाजारों के कमजोर पड़ने के प्रभाव के परिणामस्वरूप, एक सापेक्ष विकास मंदी है। समावेशी विकास हासिल करने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों के लिए निम्नलिखित समस्याएं प्रमुख हैं। वो हैं:

1. गरीबी
2. रोजगार
3. कृषि
4. सामाजिक विकास में समस्याएँ
5. क्षेत्रीय विषमताएँ।

भारत में योजना और विकास में समावेशी विकास की भूमिका

भारत में योजना और विकास में समावेशी विकास की भूमिका निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की है:

- सार्वजनिक कंपनियों की सेवा, प्रशिक्षण और पुन: रोजगार सहायता को मजबूत करते हुए, बड़ी कंपनियों द्वारा बर्खास्तगी के लिए प्रशासनिक बोझ को कम करके औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करें।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से अधिक उत्पादक कृषि क्षेत्र का समर्थन करें।
- शिक्षा क्षेत्र के भीतर जवाबदेही को मजबूत करना, और बेहतर स्कूल बुनियादी ढांचे सहित शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना।
- यह सुनिश्चित करें कि आर्थिक विकास में तेजी लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए कार्यबल के कौशल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है।

- समेकित राष्ट्रीय सूचना संरचना द्वारा समर्थित स्वास्थ्य देखभाल परिणामों के लिए जवाबदेही तंत्र की शुरुआत करते हुए, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का विस्तार करें और प्राथमिक देखभाल सेवाओं पर अधिक जोर देकर और सुनिश्चित करें कि आरएसबीवाई द्वारा कवर की गई सेवाओं को देखभाल के सभी स्तरों पर स्पष्ट रूप से परिभाषित करके लागत दक्षता सुनिश्चित करें।
- व्यापार सुगमता सुधारों को आगे बढ़ाएं, व्यापार दस्तावेजों को सरल और सामंजस्यपूर्ण बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें और घरेलू और क्रॉस-बॉर्डर एजेंसी को-ऑपरेशन को मजबूत करें।
- ब्रॉडबैंड और इंटरनेट में प्रवेश और निवेश को प्रोत्साहित करने और माल और सेवाओं में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल टेलीफोन बाजार में तय किए गए व्यापार और निवेश उदारीकरण के प्रयासों को निर्धारित करें।
- जिम्मेदार व्यापार आचरण को बढ़ावा देने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंधों को और आसान बनाने के द्वारा निवेश को बढ़ावा।
- उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अवसंरचना सेवाओं के मूल्य निर्धारण को प्रगतिशील रूप से समायोजित करें।
- स्थानीय सरकारों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त करें, और यह सुनिश्चित करें कि उच्च स्तर की सरकार क्रॉस-ज्यूरडिशनल को-ऑर्डिनेशन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें।
- पानी से अन्य कृषि-समर्थन नीतियां और बढ़ते नवाचारों का समर्थन करने की दिशा में अन्य आदानों, खेतों पर उत्पादकता और स्थिरता और जहां आवश्यक हो, संसाधन-गरीब खेतों के बीच कम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि समावेशी विकास में अनिवार्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में सरकार की बढ़ती भूमिका के साथ भारत के राजकोषीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और विचलन और विकेन्द्रीकरण को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धी दबावों को मजबूत करना, कार्यबल संरचना को बदलना, आकार और मानव संसाधन शामिल हैं। प्रबंधन की व्यवस्था, बजट प्रथाओं और प्रक्रियाओं को बदलना, और बजट और प्रबंधन के लिए परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोणों को पेश करना जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता बढ़ जाती है ताकि विभिन्न विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सरकार की बेहतर नीति के प्रति प्रतिक्रिया के साथ, सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक अच्छी तरह से काम कर रहे वित्तीय ढांचे के साथ एक अनुकूल वातावरण अन्य प्रासंगिक हितधारकों की मदद कर सकता है और अर्थव्यवस्था पर व्यापक आधारित प्रभाव प्राप्त कर सकता है।

चूंकि समावेशी विकास को सरकार द्वारा एक प्रमुख ध्यान देने के रूप में माना जाता है, इस संबंध में नीतिगत सुधार उद्योगों और बाजार पर एक महत्वपूर्ण अभी तक व्यापक प्रभाव डालते हैं। सिस्टम के सभी खिलाड़ी अपने व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर एक निश्चित मामले में प्रभावित होते हैं। आज के परिदृश्य में, उन सभी वैश्विक घटनाओं के बीच, जो हम एक वित्तीय कोण से घरेलू प्रचलित कारकों को देखते हैं जो व्यवसायों को चलाते हैं और बड़े पैमाने पर बाजारों और अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।